दैनिक जागरण
स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है

जहरीली शराब का कहर

सहारनपुर के निकट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर अनेक गांवों में जहरीली शराब ने जैसा कहर ढाया उससे एक बार फिर यह पता चल रहा है कि शराब बिक्री से अपना खजाना भर रही राज्य सरकारें मिलावटी और जहरीली शराब के अवैध कारोबार से किस तरह आंखें मूंदे रहती हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जहरीली शराब से दर्जनों लोग मर जाएं और फिर भी पुलिस-प्रशासन यह बताने की स्थिति में न हो कि इतने लोग किसकी लापरवाही से काल के गाल में समा गए? इससे तनिक भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि जहरीली शराब के एक और कहर के बाद यह कहा जा रहा है कि अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा जा रहा है और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यदि मौत के इस काले कारोबार के खिलाफ वास्तव में सख्ती बरती जा रही होती तो इतनी बड़ी घटना घटती ही नहीं। अगर यह माना जा रहा है कि जहरीली शराब के कहर ढाने के बाद दिखाई जाने वाली सक्रियता से अवैध शराब का कारोबार थम जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसकी गवाही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वे ग्रामीण इलाके दे रहे हैं जहां जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन किस तरह पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखता, इसका प्रमाण यह है कि जिस इलाके में जहरीली शराब ने कहर ढाया उसी इलाके में दस साल पहले भी करीब 50 लोग मिलावटी शराब पीकर मर गए थे। जहरीली शराब पीकर मरने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वे रह-रह कर भेड़-बकरियों की तरह मरते रहें।

यह शराब बिक्री के तंत्र के नियमन की कमी का दुष्परिणाम है जिसके चलते मिलावटी शराब का धंधा बिना किसी रोक-टोक चलता रहता है। इस तरह के धंधे में लिप्त लोग जब-जब ज्यादा कमाई के लालच में आते हैं तब-तब लाशों के ढेर लग जाते हैं। आखिर यह एक तथ्य है कि करीब आठ महीने पहले कानपुर में जहरीली शराब से एक दर्जन मौतें हुई थीं। यह भी कल-परसों की ही बात है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जहरीली शराब ने कहर ढाया। इसका मतलब है कि दोनों राज्यों में अवैध शराब का धंधा मनमाने तरीके से चल रहा है। अवैध शराब के धंधे में कोई रोक न लगने की बड़ी वजह राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी है। दुर्भाग्य यह है कि इस कमी का परिचय अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है। यही कारण है कि देश के किसी न किसी हिस्से से जहरीली शराब से मौतों के समाचार आते ही रहते हैं। मिलावटी या फिर अवैध तरीके से बनाई जा रही शराब कभी भी जानलेवा हो सकती है। इस तरह से शराब बनाने-बेचने का धंधा तब तक बंद होने वाला नहीं जब तक इस धंधे के मूल कारणों का निवारण नहीं किया जाएगा। समझना कठिन है कि आखिर मौत के इस धंधे को बंद करने में कोताही का परिचय क्यों दिया जाता है? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से भी चाहिए और उत्तराखंड की सरकार से भी।

कांग्रेस के करीब माकपा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी मुहिम का समर्थन करने के बावजूद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ पार्टी का कोई तालमेल नहीं होगा। राहुल गांधी के साथ बैठक करने के बाद बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि राज्य में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल के बीच कोई तालमेल नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने वाममोर्चा के साथ चुनावी तालमेल का विकल्प खुला रखा है। वाममोर्चा की ओर से चुनावी गठबंधन का प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस इसपर विचार करेगी। बंगाल कांग्रेस ने राहुल गांधी को वाममोर्चा के साथ तालमेल करने की सलाह भी दी है। यह बात दूसरी है कि इस दिशा में वाममोर्चा ने अभी कोई पहल नहीं की है। वाममोर्चा और कांग्रेस बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। दोनों विपक्षी दल चिटफंड घोटाले से लेकर अन्य ज्वलंत मुद्दों पर ममता सरकार को घेरने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से सीबीआइ द्वारा पूछताछ करने के प्रयास पर ममता जब केंद्र से भिड़ीं और उसके बाद धरने पर जाकर बैठ गईं, तब भी उन्हें प्रदेश कांग्रेस और माकपा का समर्थन नहीं मिला था। उल्टे प्रदेश कांग्रेस और माकपा ने इस मुद्दे पर अपने-अपने ढंग से ममता की आलोचना की थी। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की बैठक में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान भी उपस्थित थे। मन्नान घोर ममता विरोधी हैं। वह पहले से ही विधानसभा में माकपा विधायक दल के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं। मन्नान वाममोर्चा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती को साथ लेकर विधानसभा में हमेशा ममता सरकार पर हमलावर रहे हैं। मन्नान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर ही राज्य में चिटफंड घोटाले की सीबीआइ जांच शुरू हुई थी। राहुल गांधी के ममता के धरने पर बैठने का समर्थन करने के बावजूद मन्नान राज्य सरकार का विरोध करने से पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि भाजपा के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, उसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं।

राजनीति के साये में भ्रष्टाचार की जांच

संजय गुप्त

ऐसी किसी व्यवस्था का निर्माण आवश्यक हो गया है कि पुलिस और सीबीआइ समेत अन्य जांच एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सकें

पिछले दिनों सारधा चिटफंड घोटाले में सुबूत मिटाने-छिपाने के आरोपों से घिरे कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने की सीबीआइ की कोशिश के दौरान जैसा हंगामा और तमाशा हुआ उससे पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ ही देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआइ की भी फजीहत ही हुई। इस शर्मनाक घटनाक्रम से बचा जाना चाहिए था। कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से सीबीआइ की पूछताछ की कोशिश के दौरान हुए तमाशे का जैसा राजनीतिकरण हुआ वह भी बहुत बेहद अरुचिकर रहा। एक ओर जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह सीबीआइ के जरिये उन्हें परेशान करना चाह रही है वहीं केंद्र सरकार और भाजपा ने उन पर यह आरोप मढ़ा कि वह सीबीआइ की जांच रोकने के लिए अपने संवैधानिक दायरे का उल्लंघन कर रही हैं। ममता बनर्जी सीबीआइ अधिकारियों को अपनी पुलिस के हाथों बंधक बनाने के बाद जिस तरह धरने पर बैठीं वह अभूतपूर्व रहा। इसके पहले शायद ही कभी किसी राज्य की पुलिस ने सीबीआइ अफसरों को बंधक बनाया हो। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह रही कि बंगाल पुलिस की इस अतिवादी हरकत और धरने पर बैठीं ममता बनर्जी का अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन करने में देर नहीं लगाई। यह समर्थन केवल इसीलिए किया गया ताकि खुद को मोदी सरकार के खिलाफ दिखाया जा सके। इस सबसे संघीय ढांचे की एक बेहद खराब तस्वीर सामने आई। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि यह तस्वीर तब सामने आई जब भाजपा नेताओं की रैलियों को लेकर मोदी और ममता सरकार के बीच तनातनी जारी थी।

यह समझ आता है कि सारधा घोटाले की जांच के क्रम में सीबीआइ कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीते चार सालों में यह पूछताछ क्यों नहीं हो सकी? यह पहली बार नहीं जब सीबीआइ के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप उछला हो। इस तरह के आरोप तब भी उछलते थे जब मनमोहन सरकार थी। ऐसे आरोपों के बीच इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि कोलकाता पुलिस आयुक्त ने सीबीआइ के उन नोटिस का संज्ञान नहीं लिया जो उन्हें जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए थे। सीबीआइ अधिकारी जब उनसे पूछताछ करने पहुंचे तब तक ऐसा माहौल बना दिया गया कि वह उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जहां सीबीआइ यह दावा कर रही थी कि पुलिस आयुक्त राजीव कुमार लापता हैं वहीं बंगाल सरकार कह रही थी कि वह फिलहाल छुट्टी पर हैं। पता नहीं सच क्या था, लेकिन यह तो एक तथ्य ही है कि सीबीआइ सारधा और रोज वैली चिटफंड कंपनियों की ओर से किए गए हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रही है। इन दोनों घोटालों में आम लोगों के करीब 20 हजार करोड़ रुपये का गबन हुआ है। इन घोटालों की जांच में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। कुछ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक समय सारधा घोटाले की जांच कोलकाता के मौजूदा पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने विशेष जांच दल के प्रमुख के तौर पर की थी। सीबीआइ की मानें तो वह सारधा घोटाले के कुछ अहम सुबूत छिपाए हुए हैं और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ आवश्यक है। इसके विपरीत ममता बनर्जी उन्हें काबिल अफसर बताकर उन्हें सीबीआइ जांच से बचाती दिख रही थीं। आखिरकार जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी, लेकिन उन्हें सीबीआइ के शिलांग दफ्तर में पेश होने को कहा। इस फैसले को सीबीआइ और बंगाल सरकार अपनी-अपनी जीत बता रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो यही दिखेगा कि इस फैसले से ममता सरकार की किरकिरी हुई। शायद यही कारण रहा कि ममता बनर्जी धरना खत्म करने को बाध्य हुईं।

यह समय ही बताएगा कि सारधा घोटाले में तृणमूल नेताओं की संलिप्तता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इतने बड़े घोटाले राजनीतिक संरक्षण से ही होते हैं। आवश्यकता केवल यह पता लगाने की ही नहीं है कि सारधा या फिर रोज वैली कंपनियों के संचालकों को किस हद तक किन नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, बल्कि इसकी भी है कि क्या उन्हें पुलिस अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त था? इसकी तह तक जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी कोलकाता के पुलिस आयुक्त का उस तरह बचाव कर रही हैं जैसे वह तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी हों। समझना कठिन है कि वह और साथ ही चार अन्य पुलिस अधिकारी ममता के साथ धरने पर क्यों बैठे? हैरत नहीं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यह चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि राज्य सरकार ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी उनका बचाव करने को लेकर अडिग दिख रही हैं। यह तो पुलिस का खुला राजनीतिकरण ही है। पता नहीं इस मामले में आगे क्या होता है, लेकिन पुलिस का इस हद तक राजनीतिकरण ठीक नहीं कि उसके वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठें। निःसंदेह यह भी ठीक नहीं कि सीबीआइ इस तरह के आरोपों से घिरी रहे कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगने से उसकी साख को चोट ही पहुंचती है।

पता नहीं सारधा घोटाले का सच क्या है, लेकिन यह अजीब है कि अपने देश में विशिष्ट व्यक्तियों से पूछताछ का तरीका भी विशिष्ट है। एक आम आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति बार-बार समन देने पर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते। जब कभी वे हाजिर होते हैं तो उनके पास ऐसे अदालती आदेश होते हैं कि उन्हें अमुक-अमुक तिथि तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह आम और खास लोगों के बीच किया जाने वाला भेदभाव नहीं तो और क्या है? आखिर गंभीर आरोपों का सामना कर रहे विशिष्ट व्यक्तियों को जैसी सुविधा मिलती है वैसी ही आम लोगों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

भारत आज अगर एक गरीब देश है तो इसका एक कारण भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से रोकथाम न लग पाना है। इस नाकामी के लिए पुलिस और सीबीआइ के साथ अन्य उन जांच एजेंसियों का सही तरह से काम न करना है जिन पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है। सारधा घोटाले की जांच जिस धीमी गति से हो रही है उससे आम जनता के बीच कोई सही संकेत नहीं जाता। इतने बड़े घोटाले की सुस्त गति से जांच होने और आम चुनाव के पहले उसमें तेजी आने से तो यही लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए पहले जांच धीमी गति से होती रही और फिर उसमें तेजी लाई गई। सच्चाई जो भी हो, ऐसी किसी व्यवस्था का निर्माण अति आवश्यक हो गया है कि पुलिस और साथ ही सीबीआइ समेत अन्य जांच एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें। बिना ऐसा किए भ्रष्टाचार के मामलों की सही तरह से जांच होना संभव नहीं दिखता।

अवधेश राजपूत

response@jagran.com

न कुछ करना-न धरना

सूर्यकुमार पांडेय

अगर धरने में कुछ करना-धरना होता भी है तो बस अपने शरीर को एक स्थान विशेष पर धरना होता है

एक बार फिर चतुर विक्रम शातिर बेताल को अपनी पीठ पर लादकर अपने राज्य की ओर चल दिया। बेताल ने अपनी चिर परिचित शैली में कहानी आरंभ की-'सुन राजन! तू स्वयं को बहुत कर्मठ, शक्तिशाली और सदाचारी समझता है, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं समझता हूं। आज भी तुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे अन्यथा मैं फिर तेरे हाथ नहीं आऊंगा। अच्छा, चल बता! किसी लोकतंत्र में विपक्ष के पास कौन-कौन से महत्वपूर्ण औजार होते हैं?' विक्रम बोला- 'बेताल! तुम्हारा यह सवाल निहायत ही बचकाने किस्म का है। वैसे वे हैं तो बहुत सारे, किंतु इनमें से अकारादि क्रम में अनशन, घेराव, धरना, प्रदर्शन और बंद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनमें कौन सा औजार श्रेष्ठ है, इसका निर्धारण प्रयोगकर्ता द्वारा सही समय पर इस्तेमाल और वह जिस कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है उसके सात्विक लक्ष्य में निहित होता है।' बेताल ने कहा, 'राजन! तुम्हारा उत्तर संतोषजनक है, लेकिन मैं अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा बता। अनशन में होता क्या है?' विक्रम बोला, 'अनशन में अनशनकर्ता के शरीर को भूख-प्यास झेलनी पड़ती है। बाद में किसी विशिष्ट व्यक्ति के हाथों से एक गिलास नींबू पानी या मौसम्मी का जूस इसकी निवृत्ति का कुल जमा हासिल हुआ करता है। यह कई प्रकार का होता है जैसे आमरण अनशन, क्रमिक अनशन, एक दिवसीय अनशन आदि। कभी अनशन को सत्याग्रह भी कहा जाता था। आज समय के साथ इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि अब कोई भी सत्य के आग्रह के लिए अनशन नहीं करता है। यह हर किसी से सधता भी नहीं है। इसके लिए शरीर का व्याधिमुक्त होना अनिवार्य शर्त है। यदि कोई मधुमेह रोगी दूसरों की देखादेखी उपवास करने बैठ जाए तो उसे जल्द अस्पताल का मुंह देखना पड़ जाता है।'

बेताल ने पूछा, 'और यह घेराव क्या होता है?' विक्रम बोला, 'यह अपनी उचित या अनुचित मांग मनवाने के लिए भीड़ द्वारा की जाने वाली सामूहिक क्रिया है। इसमें जिसका घेराव किया जाता है उसकी जान को सांसत में डाला जाता है। भीड़ उसे घेर लेती है और अपनी बात मनवाने के लिए उचित-अनुचित दबाव भी डालती है। घेराव प्रायः कुछ घंटों में समाप्त हो जाता है, क्योंकि या तो इसे बलपूर्वक समाप्त करा दिया जाता है या फिर तत्काल समाधान न मिल पाने की अवस्था में घेराव करने वालों का खुद का ही धैर्य जवाब दे जाता है।' बेताल ने अगला सवाल दागा, 'प्रदर्शन में क्या प्रदर्शित किया जाता है?' विक्रम बोला, 'प्रदर्शन एक सामूहिक कर्म होता है। इसे कोई अकेला करना चाहे तो वह स्वयं ही प्रदर्शनीय हो जाता है। ऐसे प्रदर्शनकारी के नोटिस शासन-प्रशासन तो दूर, आसपड़ोस के लोग भी नहीं लेते। इसमें नारेबाजी होती है और सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ भी संभव है। यह बहुत खतरनाक औजार है। कभी-कभी यह उसके आयोजकों के हाथ से निकल कर असामाजिक तत्वों के हाथ में चला जाता है। और बेताल सुन! इससे पहले कि तू मुझसे बंद के विषय में पूछे, मैं खुद बताए देता हूं-बंद का अपना गुणधर्म होता है। इसके 'अनुष्ठान' से पहले बंद का 'आह्वान' करना होता है। विशेषज्ञों का सहयोग भी चाहिए। कुछ सामग्री भी अपेक्षित होती है जैसे पुराने टायर, जिन्हें बीच सड़क पर जलाया जा सके। बंद में अराजकता संग बोनस रूप में प्रदूषण प्राप्ति भी होती है।'

बेताल ने अगला प्रश्न किया, 'राजन! अब लगे हाथ मुझे धरना के बारे में भी बता दे। साथ ही यह भी बता कि इन औजारों में से श्रेष्ठ कौन है?' विक्रम ने कहा, 'मुझे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी ज्ञात है, किंतु तुम भी मुझे एक वचन दो कि यदि मैंने तुम्हारी शंका का निवारण कर दिया तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तो सुनो बेताल! लोकतंत्र के इन सभी औजारों में से सबसे सरल और सात्विक औजार है धरना। इसमें न कुछ करना होता है, न धरना होता है। अगर कुछ करना-धरना होता भी है, तो बस अपने शरीर को एक स्थान विशेष पर धरना होता है। कुछ लोग कुर्सी पर पसरकर ही धरना देते हैं। कई लोग गावतकिया और मसनद पर अपना आसन जमा लेते हैं। वैसे सबसे उत्तम धरना जमीन पर बैठकर दिया जाने वाला होता है। किंतु यह इस पर भी निर्भर करता है कि धरना देने वाली की ममता किसी के प्रति जगी या नहीं? यदि उसके साथ उस धरने में धरना रोकने वाले भी शामिल हो जाएं तो उसका रंग और भी चोखा हो जाता है।'

बेताल ने कहा, 'राजन! तूने सही उत्तर दिया है, लेकिन मेरी भी एक विवशता है। मैं जो भी कहता हूं, उससे मुकर जाया करता हूं। मेरी प्रतीक्षा कर। चाहे तो प्रतीक्षा करते हुए धरना, बंद आदि का आयोजन कर।

response@jagran.com

ऊर्जा

राजधर्म

धर्म और राजनीति को लेकर आज जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे दोनों पर ही प्रश्न उठ रहे हैं। इसमें कभी धर्म पर राजनीति हावी हो जाती है तो कभी राजनीति अधर्म का शिकार। निहित स्वार्थों के चलते धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म के उचित-अनुचित हस्तक्षेप ने न तो धर्म की गरिमा को कहीं का छोड़ा है और न राजनीति की ही मर्यादाएं बची हैं। दोनों के प्रतिनिधि बस एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। धर्म और राजनीति का समाज के साथ रिश्ता क्षीण हो रहा है। धर्म और राजनीति एक दूसरे की सीमा में शरणागत ही लगते हैं। भारत के अतीत में धर्म संबंधों की बात करें तो, राजतंत्र हमेशा से धर्माश्रित था। धर्म एक अलिखित संविधान होता था जिसका पालन राजतंत्र समाजहित में करता था। राजतंत्र के प्रतिनिधि धर्म के गर्भ में जन्मे संविधान का सम्मान करते थे।

वेदों में जोर दिया गया है कि धर्म और राजनीति का मर्म अच्छे मनुष्य को तैयार करना है। ऐसे संस्कार पैदा करना है, जो समाज को जोड़ने की बात करें। महर्षि जाबालि मानते थे कि नास्तिक भी धर्म के साथ रहता है, भले ही उसका धर्म सर्वसमाज द्वारा स्वीकार न हो। वेद और उपनिषदों की धाराएं मनुष्य मात्र को सामूहिकता में ले जाने का प्रवाह हैं। धर्म का अर्थ किसी विचारधारा विशेष के प्रति आंखें मूंद कर चलना नहीं है। जागरूकता ही धर्म है। धर्म कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। आंखें बंद करके ध्यान लगाना धर्म नहीं है। उस राजतंत्र पर शत्रु का कब्जा हो जाता है जिसके प्रतिनिधि खंड-खंड पाखंड पर्व मनाते हैं और प्रजा की तकलीफों की चिंता नहीं करते। राजतंत्र जब तक यह नहीं समझता कि धर्म और आस्था से जोड़कर ही विश्व कल्याण की कल्पना की जा सकती है, तब तक अस्थाई परिवर्तन ही होंगे। राज्य का बुनियादी चरित्र नहीं बदलेगा। आस्थाएं परिवर्तनशील हैं, लेकिन धर्म कभी नहीं बदलता। सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था तभी सशक्त होती हैं, जब इसे धर्म का समर्थन मिलता है। वेद हमें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना अमूल्य है और आज सभी धर्मों को यही समझने की जरूरत है। पुरातनपंथी विचार कहकर हम वेदों को हाशिए पर भले ही डाल दें, लेकिन राष्ट्रधर्म के संदर्भ में वेदों की प्रासंगिकता को कभी नहीं नकारा जा सकता।

योगीराज श्रीरमेशजी महाराज

तथ्य-कथ्य | विश्व में इस्पात का उत्पादन (हजार टन में) (दिसंबर 2018)

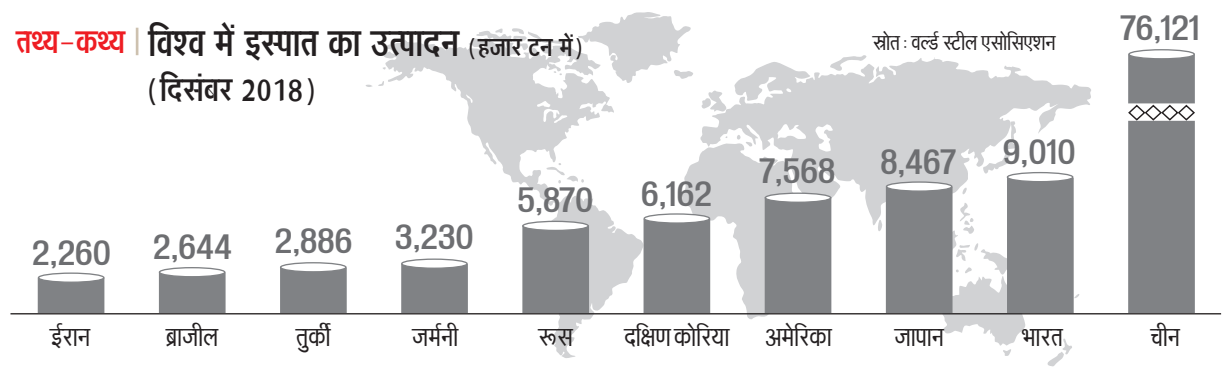

बदल जाएगी समुद्रों की रंगत

मुकुल व्यास

समुद्रों का हरा-नीला रंग और गहरा होने से समुद्री खाद्य शृंखला के साथ ही समूचा पारितंत्र प्रभावित होगा

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का नीला और हरा रंग इस सदी के अंत तक और अधिक नीला और हरा हो जाएगा। समुद्र का रंग इस पर निर्भर करता है कि पानी में मौजूद कोई भी चीज किस प्रकार सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है। रंगों में परिवर्तन मुख्य रूप से समुद्रों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की आबादी पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की वजह से हो रहा है। ये जीव फाइटोप्लैंकटन कहलाते हैं। ये जीव सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण के जरिये रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। फाइटोप्लैंकटन में मौजूद क्लोरोफिल प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले भाग को अधिक और हरे भाग को कम सोखता है। इससे हरी रोशनी परावर्तित होती है। अतः समुद्र के जिस हिस्से में ज्यादा फाइटोप्लैंकटन होंगे वहां हरा रंग दिखेगा। समुद्र के जिन हिस्सों में ये जीव नहीं होंगे वे नीले दिखाई देंगे। रंगों में परिवर्तन समुद्रों में पाए जाने वाले अन्य रंगीन पदार्थों के स्तर पर पड़ रहे प्रभावों से भी हो रहा है। ब्रिटेन की साउथंपटन यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता और इस अध्ययन की सह-लेखिका डॉ. एना हिकमैन ने कहा कि समुद्रों में फाइटोप्लैंकटन भी हरे होते हैं। अतः उनकी विभिन्न किस्में और उनकी मात्रा समुद्र की सतह के रंग को प्रभावित करती है। इन जीवों के स्तर में परिवर्तन का पता लगाना बहुत महत्व रखता है। दुनिया में होने वाली कुल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में करीब आधा हिस्सा इन सूक्ष्म पौधों का है। ये पौधे समुद्री खाद्य नेटवर्क के आधार हैं।

हिकमैन और उनके सहयोगियों ने 'नेचर कम्युनिकेशंस' में प्रकाशित अपने अध्ययन में बताया कि उन्होंने कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने यह भी पता लगाया कि इन परिवर्तनों का समुद्री सतह पर प्रकाश के सोखे जाने और उसके परावर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नतीजों से पता चलता है कि यदि दुनिया में समुद्र की सतह के तापमान में वर्ष 2100 तक तीन सेल्सियस की वृद्धि होती है तो उत्तरी अटलांटिक सहित आधे से ज्यादा समुद्रों का रंग बदल जाएगा। ये परिवर्तन फाइटोप्लैंकटन की आबादी में बदलाव को दर्शाते हैं। ये बदलाव ध्रुवों के निकट समुद्री बर्फ के कम होने, तापमान में वृद्धि और समुद्री जल के कम मिश्रण के कारण हो रहे हैं। समुद्री रंग के परिवर्तन पर नजर रखकर हम फाइटोप्लैंकटन की आबादी में होने वाले परिवर्तनों के पूर्व संकेत हासिल कर सकते हैं।

इस बीच 'नेचर क्लाइमेट चेंज' पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्तरी गोलार्ध की झीलें अपना बर्फीला आवरण खो रही हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक हजारों झीलें जो सर्दियों में जम जाती थीं अब तेजी से पिघल रही हैं। झीलों से गायब हो रही बर्फ का उन लाखों लोगों पर असर पड़ेगा जो उनके आसपास रहते हैं। सर्दियों की बर्फ के अभाव में झीलें साल में जल्दी गर्म होने लगती हैं। जल की सतह गर्म होने से झील के भीतर ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। पानी का तापमान बढ़ने से मछलियों की प्रजातियों पर असर पड़ता है। मनुष्य भी जमी हुई झीलों से लाभान्वित होता है। इससे कई और गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

सिफारिशी पत्र

चुनावों की घोषणा में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए कई सांसदों और मंत्रियों ने अब तक उनके दफ्तर में पड़े सिफारिशी पत्रों को तेजी से निपटाना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ पत्र ऐसे हैं जिनमें उनसे किसी कार्य को कराने की गुजारिश की गई है जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किसी दूसरे मंत्री के पास भेजना है। एक राज्य मंत्री के कार्यालय का स्टाफ आजकल इसी में लगा हुआ है। अब तक जो पत्र उनके दफ्तर में पड़े धूल फांक रहे थे, अचानक उन्हें उनकी सुध आ गई है। बताया जाता है कि मंत्री महोदय ने स्टाफ को कहा है कि फरवरी के अंत तक सभी पत्रों के जवाब और जिस चिट्ठी को जहां भेजा जाना है, वहां भेज दिया जाए। बहरहाल मंत्रीजी को चिट्ठी लिखने वाले का भला होगा या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि नेताजी अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री जरूर कर लेंगे।

आंकड़ों पर नाराजगी

रोजगार के आंकड़ों पर बचाव करने के सिलसिले में नीति आयोग का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है। सरकार में कोई आयोग के इस प्रदर्शन पर खुश नहीं है। खासतौर पर उपाध्यक्ष राजीव कुमार को लेकर सरकार से लेकर पार्टी तक में नाराजगी है। एनएसएसओ के एक सर्वे में रोजगार के आंकड़ों को लेकर मचे बवाल के बाद नीति आयोग उसके बचाव में उतरा था, लेकिन पत्रकारों के समक्ष अपनी बात दावे के साथ रखने में पूरी तरह विफल रहा। यही वजह रही कि पार्टी को अपने अन्य नेताओं को संकटमोचक बनाकर मीडिया के बीच उतारना पड़ा। ऐसे ही एक नेता का कहना था कि अर्थशास्त्री होने के बावजूद कुमार रोजगार के आंकड़ों पर सरकार का बचाव नहीं कर पाए तो वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का पक्ष कैसे रखेंगे?

छह महीने का सुख

चुनाव की बेला आते ही सरकार पर जनाकांक्षाएं पूरी करने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। इस चक्कर में उन जन प्रतिनिधियों की भी सुनी जाने लगी है, जिन्हें पहले कोई पूछता नहीं था। फिर चाहे मंत्रालय रेल का हो या कि सड़क का अथवा फिर कोई और। अब रेलवे के उदाहरण पर भी गौर करते हैं, पिछले कुछ महीनों से यहां नई ट्रेनें चलाने और स्टॉपेज देने के मांग पत्रों की बाढ़ आई हुई है। कुछ पत्रों में ट्रेनों के फेरे बढ़ाने अथवा मार्ग विस्तार करने की याचना है। जबकि नौकरी और ट्रांसफर, पोस्टिंग की सिफारिशें इनसे अलग हैं। चुनाव के मद्देनजर रेलवे बोर्ड उदारतापूर्वक इन पर विचार भी कर रहा है और यथासंभव मांगें मानी जा रही हैं। लेकिन मांगों का दायरा इतना बड़ा है कि सबको संतुष्ट करना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में सबको अस्थाई रूप से खुश करने करने का फार्मूला अफसरों ने सुझाया है। उन्होंने छह महीने के लिए प्रयोगात्मक रूप से सभी स्टॉपेज को मंजूरी देने का आइडिया दिया है। इससे फिलहाल काम चल जाएगा। चुनाव बाद समीक्षा कर इनमें से तमाम स्टॉपेज को यह कहकर बंद किया जा सकता है कि इनसे रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था। इस विचार पर अमल भी शुरू हो गया है।

उतार-चढ़ाव का चक्र

जिंदगी में उतार-चढ़ाव का चक्र एक तरह से शाश्वत माना जाता है। कभी न कभी हर व्यक्ति को इस चक्र के दोनों पहलुओं से रूबरू होना पड़ता है। मगर उतार-चढ़ाव का यह चक्र राजनीति में जितनी तेजी से बदलता है उतना शायद ही किसी दूसरे क्षेत्र में। तभी नेताओं को उतार-चढ़ाव का भय भी ज्यादा रहता है। सोलहवीं लोकसभा अपने आखिरी मुकाम पर है और केवल तीन दिन की बैठक शेष है। तभी दर्जनों सांसद इन दिनों संसद भवन की अपनी स्मृतियों को कैमरे में कैद करते हुए तो दर्जनों अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को संसद भवन परिसर की सैर कराते नजर आ रहे हैं। चुनावी इतिहास गवाह है कि हर नई लोकसभा में लगभग आधे मौजूदा सदस्य दोबारा जीतकर नहीं आते। जाहिर तौर पर तमाम सांसद भी इस इतिहास को देखते हुए सत्रहवीं लोकसभा का मुंह देख पाएंगे या नहीं इसे लेकर सशंकित हैं। जब मन में ऐसी शंका हो तो अपने इतिहास की स्मृतियों को सहेज लेने का मौका भला क्यों छोड़ दिया जाए।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *